CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported throwing of Tribals into the Subarnarekha River at Jamshedpur

MR. CHAIRMAN: Now, the Calling Attention Motion.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH (Bihar): Sir, I beg t_0 call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported throwing of some tribals, including women and children, into the Subarnarekha river by 'muscleme'n' of a contractor at Jamshedpur on the 16th August, 1978.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, the Government deplore the unfortunate incident in Jamshedpur on the 16th August, 1978 in which five persons belonging to the weaker sections of society lost their lives.

According to the report received from the Government of Bihar, **the** Tata Iron & Steel Company Ltd. awards annual contract for the right to pick iron scraps from their slag dumps in Jamshedpur. On the 16th August, men employed by the contractor to guard the slag dump chased away some persons who were picking iron scraps from the dump. Some of them were assaulted and thrown into the nullah which meets the Subarnarekha river about 250 yards from the slag dump. Many managed to swim across the nullah, but some of them got drowned. Two dead bodies were recovered on the 16th itself and three on the following day. Two of the dead belonged to Scheduled Tribes, two to Scheduled Castes and one to a backward class. Further intensive search for bodies resulted in the recovery on the 17th August of one more dead body of a two-year child in a highly decomposed state on the bank of Subarnarekha river. No one has so far come forward to claim this body. According to the State Government, this death does not appear to be connected with the previous day's incident.

The Police reached the spot immediately on receipt of information and could effect some arrests then and there. The Commissioner, Additional IGP(CID), Deputy Commissioner, D.I.G., S.P. and other senior revenue and police official have also since visited the spot. A case under sections 148/149/302/201/109 I.P.C. was registered against the contractor's men. Office premises of the contractor were raided on the same day and some ammunition kept there unauthorisedly was recovered. A case under the Arms Act was, therefore, registered. In all, 22 persons have been rounded up so far in connection with these two cases. Processes for compelling the attendance of two absconders have also obtained from the court and their property has been attached. The action of the local administration following the incident was quick and effective and relief to the affected families was provided in cash and kind.

The Chief Minister has announced *ex-gratia* grant of Rs. 5,000 to each of the bereaved families.

The situation is reported to be under control and returning to normal. However, there are certain implications of this incident, such as the contractual system of disposal of these items, the suitability of such a system in a tribal area involving relationship with the tribes and their exploitation and the policy of the Undertaking towards the disposal of slags, which required attention. Government have these issues under consideration.

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, जमशेदपुर की घटना जिसकी ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, इससे शर्मनाक, बर्बरतापूर्ण और जघन्य कोई

अपराध नहीं हो सकता और उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यह घटना एकाएक नहीं हो गई और ये गरीब लोग जो वहां पर थे आदिवासी, हरिजन जैसा आपने बताया, इनका मुख्य धंधा, मुख्य जीविका का आधार काफ़ी दिनों से स्क्रैप चुनना था, जिसको छाई कहते हैं। उससे वह अपने जीवन का निर्वाह करते थे और जब से यह कांट्रैक्ट सिस्टम वहां पर लागू किया उसके बाद वह कांट्रेक्टर एक मन लगभग स्क्रैप का उनको एक रुपया देते थे और एक मन स्क्रैप चुनने में पूरे एक व्यक्ति को एक दिन लग जाता है। दिन भर के लिए उसकी मजदूरी एक रुपया है। वह मजदूर काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि दो रुपया उनको मिले। आप स्वयं समझ सकते हैं श्रीमन् कि आज के समय में जमशेदपुर जैसे शहर में दो रुपया उनको मिले भी तो उसका क्या महत्व हो सकता है। छाई का पहाड़ जैसा हो गया है। दो तरफ पहाड़ है और बीच में जैसे कोई पहाड़ी का तन्द्रा होता है उस तरह का बना हुआ है। उसके आगे सुवर्णरेखा नदी है। ये कांट्रेक्टर के जो पहलवान या मिसलमैन यह मौका देख रहे थे कि वह निरीह लोग कब इनके हाथ में आयें और जब इनको मौका मिले तो उनको घेर कर मार दिया जाए। नदी में बाढ़ आई हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ़ नदी में बाढ़ आई है और दूसरी तरफ़ छाई का पहाड़ है जिसमें वह निरीह प्राणी हैं जो दो रुपया उनको मिल जाए इसके लिए लड़ रहे थे। ऐसे गरीब लोगों को घेर कर वहां कुछ लोगों ने उनको मारा और जो लोग जान बचाने के लिए भाग पड़े वह नदी में कूद कर डूब गये, बह गये। यहां श्रीमन्, 5–6 नहीं, 20 से ज्यादा लोग नदी में डूब गये या आहत हुए। इस घटना से उपसभापति महोदय सिर झुक जाता है। एक तो आप जानते हैं कि मंडल जी संयोग से बिहार से आते हैं, आपका छोटा नागपुर कितना सेंसिटिव एरिया है। यही वहां के लोगों की शिकायत रही है कि वहां के लोग हर मामले में यह समझते हैं कि वे उपेक्षित हैं। जो छोटा नागपुर को अलग करने की योजना अब चल रही है, जो आन्दोलन का रूप ले रही है, इसके बारे में भी और इसकी जड़ में भी वही सारी बातें हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका एस० पी० भी वहां है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहां है लेकिन अभी बातचीत चल रही है जबकि घटना वहां हो गई तब एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पहुंच रहे हैं। जब जयप्रकाश जी की मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें कहा था कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि 30 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसी घटनायें हो रही हैं। केवल बेलछी की घटना हुई, बिल्लुपुरम की घटना हुई, मराठवाड़ा की घटना हुई, कंझावला की घटना हुई, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि मैंने इसीलिए कहा कि यह दलगत बात नहीं है, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है, जमींदार लोग या ऐसे असामाजिक तत्व यह समझने लगे हैं कि उनके लिए उत्साह का दिन आ गया है वह चाहे जो कर सकते हैं। पहले जो एक प्रभाव था सरकार का कि हरिजनों, आदिवासियों और माइनोरिटीज की सुरक्षा के लिये सरकार कोई सख्त कदम उठायेगी वह अब खत्म हो गया है। आज लोग अपने आप को स्वतन्त्र महसूस करते हैं। उनकी यह फीलिंग है कि यह सरकार हमारी हो गई है। उनका यह सही इम्प्रेशन है या गलत यह तो आप जानते होंगे लेकिन मैं इसे सही इम्प्रेशन मानता हूं। वह यह मानते हैं कि यह सरकार हमारी है। यह जो जनता सरकार है हमारी सुरक्षा के लिये गरीबों की सुरक्षा के लिये नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों की सुरक्षा के लिये कहीं कोई बात हुई है, आदिवासियों की सुरक्षा के लिये कहीं कोई बात हुई है। जहां यह घटना घटी है वहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है। मण्डल जी

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

वहां से आते हैं वह सब जानते हैं । जब से कर्पूरी साहब मुख्य मन्त्री बने मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी बार गोलियां चलीं । कर्पूरी साहब को मुख्य मन्त्री बने 14 महीने के करीब हो गये हैं मुझे जहां तक जानकारी मिली है वहां पर लगभग 36 बार गोलियों की बौछार हो चुकी है । सिर्फ पंचायत के चुनावों में 20 बार गोलियों की बौछार हुई है । वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है । कर्पूरी साहब ने खुद स्वीकार किया है । टाइम्स आफ इण्डिया जो बाम्बे का है उसके फ्रण्ट पेज पर लिखा है । 15 अगस्त को गांधी मैदान में उन्होंने स्पीच दी है उसको मैं बता रहा हूं :

"The Bihar Chief Minister, Mr. Karpoori Thakur, today admitted his fourteen-month old Government's failure to make a headway on three major fronts—administative reforms, educational reforms and law and order."

मण्डल जी बहुत निष्पक्ष व्यक्ति बन सकते हैं इसलिये मैं चाहता हूं—वह निष्पक्षता से मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे । मैंने आपको देखा जब आप विधान सभा अध्यक्ष रूप में विराजमान थे और मैं सदस्य था आप अब गृह मन्त्री हैं इसलिये आप इस बात को देखें कि प्रजातन्त्र में अगर कोई सरकार बनती है तो उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है ? क्या उसका प्राथमिक कर्तव्य यह नहीं है कि कानून और व्यवस्था को कायम करे ? क्या यह कर्तव्य नहीं है कि जो कमजोर वर्ग हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं उनकी सुरक्षा के लिये कदम उठाये ? ये जो अत्याचार हो रहे हैं बेलछी में, जमशेदपुर में और दूसरी जगहों में, मैं छोटा नागपुर का रहने वाला हूं मैंने सब देखा है, ऐसे अत्याचार अभी तक कभी नहीं हुए थे । अब आप अगर इनको नहीं रोक सकते तो आपका सरकार में बने रहना ठीक नहीं है । आप के कर्पूरी साहब कबूल करते हैं कि तीन फ्रण्ट पर हम फैल्योर रहे हैं तब उनके लिये सत्ता में बने रहना उचित नहीं है । कर्पूरी साहब को वहां की कोई चिन्ता नहीं है । रात-दिन दिल्ली में रहते हैं । क्या उनका नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वहां की स्थिति को देखें । जब चौधरी चरण सिंह वहां बैठे थे तब भी मैंने कहा था बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है । वह कम से कम कानून और व्यवस्था को तो ठीक करे । मैं राष्ट्रपति शासन के पक्ष वाला आदमी नहीं हूं । राष्ट्रपति शासन वाली सरकार कभी अच्छी नहीं होती । लेकिन अभी कोई विकल्प नहीं दिखता ।

मैं मन्त्री महोदय से केवल दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि आपका कोई मन्त्री अभी तक वहां पहुंचा या नहीं । अक्सर यह वहां हो रहा है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो चीफ मिनिस्टर वहां नहीं जाते । जहां तक मेरा अनुमान है बेलछी में भी बहुत बाद में गये । पहले श्रीमती गांधी और हम लोग गये उसके बाद चीफ मिनिस्टर गये । एक मिनिस्टर गये थे लेकिन वह भी इधर-उधर से देख कर लौट आए । पहला प्रश्न यह है कि वहां कोई गया या नहीं और कोई गया तो कोई रिलीफ उनको दी गई या नहीं यानी कोई मुआवजा दिया गया या नहीं ? नम्बर दो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कांट्रैक्ट है उसको खत्म किया या नहीं यह कांट्रैक्ट कहां का है । यह सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है इससे देश का सिर नीचा होता है । हरिजनों को जिन्दा जलाया जाता है, आदिवासियों को जिन्दा नदी में फेंक दिया जाता है । इससे देश का सिर नीचा होता है । तीसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप महसूस करते हैं या नहीं कि बिहार में वर्तमान सरकार सक्षम नहीं है ? वहां के लोगों की सुरक्षा खतरे में है । लोगों के जान-माल की कोई हिफाजत नहीं है । इसलिये प्रेजीडेंट रूल आप वहां लागू करवाना चाहते हैं या नहीं? जनता पार्टी के लगभग 10–12 बिहार के सदस्यों ने बयान दिया है ।

अखबारों में भी छपा है। मंडल साहब भी जानते होंगे कि बाढ़ पीड़ितों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके लिये कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सुना है बिहार के मुख्य मंत्री दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं। उन्हें बिहार की कोई चिंता नहीं है वह तो राजनीति में पड़े हुए हैं। अगर वह बिहार के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको यहां पार्टी में कोई पद दे दिया जाए। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस बारे में स्पष्ट बताये कि क्या बिहार की वर्तमान सरकार वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को कायम करने में सक्षम है या नहीं ? अगर श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को कायम करने में असमर्थ है तो क्या आप कुछ अवधि के लिये वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू करके कम से कम लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने का प्रयत्न करेंगे ? इस प्रकार से मेरे तीन चार सवाल हैं जिनका मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, यह घटना शर्मनाक है, दुःखद है और जो विशेषण या संज्ञा इस घटना को दी जाये, हम उसके साथ हैं। कड़े से कड़े शब्दों में इस काण्ड की निन्दा की जानी चाहिए। यह बहुत ही निन्दनीय घटना है, इसमें हमारी कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि यह दल का सवाल नहीं है और सचमुच में यह दल का सवाल नहीं है। कोई दल अगर इस प्रकार की घटनाओं से लाभ उठाना चाहता है तो उस दल को यह समझ लेना चाहिए कि वह इस समस्या को और भी कठिन और जटिल बना रहा है और गरीब इंसानों के साथ अपनी राजनीति के लिए खिलवाड़ कर रहा है। यह बात सही है और मैं इसके साथ हूं कि इस काण्ड की जितनी निन्दा की जाये उतनी कम है।

माननीय सदस्य ने कहा कि जब से जनता पार्टी शासन में आई तब से इन लोगों में साहस बढ़ गया है। 30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा तब इनका साहस नहीं बढ़ा, लेकिन आज एकदम से इनका साहस बढ़ गया .... (*Interruptions*) श्रीमन्, जब मैं बोल रहा हूं तो ये लोग इस प्रकार से शोर मचा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राव (उत्तर प्रदेश) : आप पोलिटिकल जवाब मत दीजिये।

श्री धनिक लाल मंडल: जो बातें मैं कहीं गई हैं, अगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कि हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। मैंने यह कहा है कि यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। अगर कोई दल इसको राजनीति का प्रश्न बनाता है तो वह दुःखी मानवता के साथ अपनी राजनीति के लिये खिलवाड़ कर रहा है। इसलिये मैंने कहा कि इस काण्ड की घोर निन्दा की जानी चाहिए। अगर कोई दल गरीबी से दुःखी जनता की कठिनाइयों से अपना हाथ सेंकना चाहे तो यह निन्दनीय प्रवृत्ति है। हम सब को मिल कर इस समस्या को हल करना है। मैंने बार-बार कहा है कि विरोधी पक्ष के लोगों के साथ हमारी इस बारे में बैठकें हो ती रहती हैं। अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। हम उन लोगों का सहयोग भी इसमें ले रहे हैं और हमें उनका सहयोग मिल भी रहा है। इसलिये मैंने यह नहीं कहा है कि कोई दल इन समस्याओं से फायदा उठाना चाहता है। मेरा मतलब सिर्फ यह था कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि जब से जनता पार्टी सरकार में आई है तब से जमींदारों या ऐसे ही लोगों का साहस बढ़ गया है। ऐसी बात नहीं है। यह प्रथा आज से नहीं चल रही है। जब से यह कम्पनी कंट्रेक्ट देने लगी है उसको सात साल हो गए हैं। पहले इसकी नीलामी

[श्री धनिक लाल मंडल]

नहीं होती थी और गरीब लोग लौहे के टुकड़े चुन कर उसको बाजार में बेच देते थे। लेकिन पिछले सात वर्षों से इस कम्पनी ने थोड़े से पैसों के लिए यह काम ठेकेदार को देना शुरु कर दिया। यह बात सही है कि ठेकेदार अब आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो उस लोगों पर अत्याचार करते हैं आदिवासी गरीब होते हैं, बेबोल होते हैं, मूक होते हैं, उनके पास आवाज नहीं होती है। ऐसे लोगों के बीच में जब ठेकेदार पहुंचते हैं तो खराबी पैदा हो जाती है। एक्साइज कंट्रेक्टर भी यही करते हैं और जंगलात के कंट्रेक्टर भी आदिवासियों पर जुर्म और अत्याचार करते हैं। पिछले एक साल से यह प्रथा रही हो, ऐसी बात नहीं है। कई सालों से यह प्रथा चल रही है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बिहार) : सवाल यह नहीं है कि यह प्रथा कब से चल रही है। सवाल यह है कि कब से इतने लोग मारे जाने लगे हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : शर्मा जी, आप जिस जिले सैदाबाद से आते हैं वहां पर इमरजेन्सी के दौरान 118 आदिमियों को नक्सलवादी कह कर मारा गया है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह गलत है... (*Interruptions*)

श्री धनिक लाल मंडल : आप लोगों ने इस प्रकार के काम किये हैं... (*Interruptions*)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अपने दोषों को छिपाने के लिए गैर जिम्मेदारी की बात मत कीजिए।

श्री धनिक लाल मंडल : यह भी बिहार से आ रहे हैं और मैं भी बिहार से आ रहा हूं। आप गैर जिम्मेदारी की बात कहते हैं, मैं यह कहता हूं कि बिहार विधान सभा के फ्लोर पर मुख्य मंत्री ने कहा। आप गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। क्या आपने इतने लोगों को गोली नहीं मरवा दी उनको खत्म नहीं कर दिया... (*Interruptions*)

श्री मन्, मैं तो दलील दे रहा था ..... (*Interruptions*)

श्री प्रकाश महरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : क्योंकि पहले ऐसा हुआ है इसलिए यह किया जाए ..... (*Interruptions*)

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : मंत्री जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। माननीय सदस्यों से मेरा इतना ही निवेदन है कि यह समस्या है ..... (*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, यही मैं जवाब दे रहा हूं .... (*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपसभापति : आप जवाब दीजिए।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उपसभापति महोदय, पहले व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं यह बात सही है। मैंने यह मान लिया लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि लगातार हो रही हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। कंझावला में सन् 1970 से 1978 तक जमीन जोतते थे और उन पर फिर क्यों हमला किया गया ... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ राय : क्यों हमले बढ़े हैं, वीकर सेक्शंस पर जुल्म बढ़ रहे हैं ....

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, यदि मैं कारणों में जाने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। यह तो सामाजिक, राजनैतिक,

आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारण हैं। जीवन के हर पहलू में यह कारण घुस गये हैं। भारतीय जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो इन कारणों से अछूता हो। इसलिए मेरा इसमें जाने का उद्देश्य नहीं है। मैं इस सवाल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो इतनी बात कह रहा था कि यह सही है। इसलिए मैंने अपने मूल बयान में भी कहा है कि यह जो पहलू है महोदय, माननीय शास्त्री जी बैठे हुए हैं और भी कुछ लोग गए थे। श्री भोला पासवान शास्त्री, शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राईब्स के चेयरमैन डा० बी० डी० शर्मा, होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो बिहार सरकार के इतने अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है और बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए मैंने कहा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं... *(Interruptions)*

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप कैसे जिम्मेदार नहीं है। आप गृह मंत्री हैं।

श्री धनिक लाल मंडल: बिहार का मैं जिमेदार नहीं हूं। महोदय, मैंने अपने मूल ब्यान में कहा कि... *(Interruptions)*

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप गृह मंत्री हैं और यह आदिवासियों का मामला है। *(Interruptions)*

श्री धनिक लाल मंडल : ऐसे तो हर एक बात को इससे जोड़ सकते हैं क्योंकि जीवन एक है। आप जीवन की हर बात में सब चीजों को जोड़ देंगे इससे कोई तर्क नहीं निकलेगा। बिहार सरकार ने कितनी प्राम्प्टनेस दिखाई है। मैं आपको बतला रहा हूं। यह प्राम्प्टनेस यदि पिछली सरकार ने दिखलाई होती तो आज तक यह जो घटनाएं हैं बहुत कम हो गई होतीं। एक यह भी कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन समय पर काम करे और स्टर्न एटीट्यूड ले, कड़ाई से निबटे और समस्याओं का समाधान करे तो समस्याओं का हल हो जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। यह वर्तमान सरकार के बारे में कहा जा सकता है *(Interruptions)* आप शायद सहमत नहीं होंगे। कर्पूरी ठाकुर गरीब का बेटा है। यह सब कोई जानता है उसको कोई जमीन नहीं है, उसका घर नहीं है ...

(Interruptions) आप तो शर्मा जी जानते हैं, ऐसे तो अन्याय न कीजिए। कर्पूरी ठाकुर, गरीब का बेटा है, उसका कोई घर नहीं है ... *(Interruptions)*

एक माननीय सदस्य: यह गरीब का बेटा है... *(Interruptions)*

श्री धनिक लाल मंडल : इसीलिए आपको ईर्ष्या हो रही है कि आज गरीब का बेटा मुख्य मंत्री बना हुआ है। आप तो जनता की भी दुहाई देंगे और समाजवाद की भी दुहाई देंगे। और न जाने कितने मानव मूल्य हैं उनकी दुहाई देंगे लेकिन उसके आधार पर पर यदि कोई गरीब का बेटा मुख्य मंत्री बन जायेगा तो उसकी जड़ खोदेंगे। यह तो व्यवहार में नहीं हुआ ... *(Interruptions)*

श्री कल्पनाथ राय : बिहार में क्या हो रहा है। लाखों लोग बाढ़ में तबाह हो रहे हैं सारे बिहार के अंदर अन्न पानी के बगैर मर रहे हैं और गरीब का बेटा है? बिहार मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाय ... *(Interruptions)*

श्री धनिक लाल मंडल : गरीब का बेटा नहीं है? *(Interruptions)* कर्पूरी ठाकुर पर आज तक किसी ने कोई चार्ज नहीं लगाया है।

श्री कल्प नाथ राय : तुम हवाई जहाज पर घूमते हो, पोश होटलों में खाना खाते हो *(Interruptions)*

श्री धनिक लाल मंडल : स्वयं मैं आपको उसका हवाला नहीं देना चाहता हूं। शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब के कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट ने जो कार्यवाही की है उससे

[श्री धनिक लाल मंडल]

किसी को भी, कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, यह खुद इनकी रिपोर्ट में है ...
(*Interruptions*)

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): बिहार के आदिवासियों और हरिजनों का यह कहना है ...
(*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य: यही तो जवाब है और क्या है।...
(*Interruptions*)

श्री धनिक लाल मंडल: कर्पुरी ठाकुर पांच सौ आदमियों से रोज मिलते हैं, पांच सौ गरीबों से रोज मिलते हैं ...
(*Interruptions*)
आपको अनुभव नहीं है, माननीय सदस्या..

श्री कल्पनाथ राय: बिहार के पांच लाख लोग बाढ़ पीड़ित, मुगलसराय, गोरखपुर और देवरियां में...
(*Interruptions*)

श्री धनिक लाल मंडल: आपको मालूम है कर्पुरी ठाकुर 65 हजार वोटों से जीते थे असेम्बली में...

श्रीमती सरोज खापर्डे: बिहार के आदिवासियों का कर्पुरी ठाकुर ने...
(*Interruptions*).

श्री धनिक लाल मंडल: यह सब छोड़िये, इसलिए में कह रहा था।

श्रीमती सरोज खापर्डे: कुछ नहीं किया।

श्री धनिक लाल मंडल: इसलिए श्री तिवारी का वक्तव्य निकला है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा: बिहार बाढ़ में डूब रहा है और उसके मुख्य मंत्री जी दिल्ली में समझौता करा रहे हैं ...
(*Interruptions*)

श्री धनिक लाल मंडल: दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हो रही है। छोड़िये इस बात को। अच्छा श्रीमन...
(*Interruptions*)

श्री उपसभापति: इस पर ही चर्चा कीजिए।

श्री कल्प नाथ राय: 15 दिनों से बिहार डूब रहा है, बिहार में बाढ़ आयी हुई है और बिहार के मुख्य मंत्री कर्पुरी ठाकुर आज दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। बिहार के मुख्य मंत्री कौन सा काम कर रहे हैं। 15 दिनों से 50 लाख लोग डूबे हुए हैं, करोड़ों की फसल नष्ट हो रही है। बिहार का मुख्य मंत्री गैर-जिम्मेदार है, वहां मंत्रिमंडल बर्खास्त किया जाये। बिहार में चुनाव कराये जाये, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय। बिहार के बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की जाए।

श्री उपसभापति: उत्तर तो आने दीजिए।

श्रीमती सरोज खापर्डे: श्रीमन् मंत्री महोदय को कर्पुरी ठाकुर की दलील इस तरीके से करने के बजाय वह यह कर्पुरी ठाकुर जी को कहें कि मैं यह कहूंगा कि आदिवासियों और हरिजनों के प्रति जो अन्याय हो रहा है ... (*Interruptions*).
उसको दूर करें।

श्री पीलू मोदी (गुजरात): बहुत खूब अब सरोज मिनिस्टर बन गयी हैं।

श्री धनिक लाल मंडल: श्रीमन, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि 20 लोगों की मृत्यु हुई है, यहां 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। हमारी जो जानकारी है महोदय, वह यह है कि पांच लोगों की मृत्यु हुई है, पांच लोग डूब कर मर गये हैं और हमारी जो जानकारी है उसका पुख्ता आधार है। जब पुलिस को यह सूचना मिली तो काफी छानबीन की गयी, पूरे नाले को दिखलवाया गया और जो एफ०आई० आर० में पांच लोगों के नाम हैं उन सबों की लाशें बरामद कर ली गयी हैं। फिर भी यदि किसी को कोई सन्देह हो—वहां अपील की गयी है, हमारे स्थानीय अधिकारियों ने अपील की है लोगों से कि यदि कोई अभी भी मिसिंग हो, लापता हो और उसकी सूचना दी जायें तो उसकी हम लोग जांच करवायेंगे। यह हम लोगों का कहना है। ऐसे ही महोदय जो मौके पर जो काम करना था जो घटनायें

हो गयी उसका सबको अफसोस है और होना भी चाहिए । लेकिन मौके पर जो काम हो सकता था वह सब काम किया गया, उनको रिलीफ देने का जितना काम है वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किया गया । और मुख्य मन्त्रीजी ने.. (*Interruptions*) सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए तो आपको अपनी बात कहने में सुविधा होगी । आप पहले पूरी बात सुन लीजिए मैं सूचना दे रहा हूं । आपको एक तरफा सूचना है, दो तरफा सूचना होने से आपको अपनी बात कहने में और सुविधा होगी, आपकी बातों में दम हो जायेगा । मैं सूचना दे रहा हूं, आप सूचना ले लीजिए । आपको तो समय है ।

महोदय मैं यह कह रहा था कि मौके पर जो भी काम होना चाहिए वह हुआ और आगे के लिए उस पूरी चीज का रिव्यू किया जायगा और आगे क्या नीति होनी चाहिए इसके सम्बन्ध में हम जरूर विचार करेंगे कि कम्पनी को जो कन्ट्रेक्टिव प्रथा है, यह जो नीलाम करते हैं, कन्ट्रेक्टर्स को रखते हैं और कन्ट्रेक्टर मसलमैन को रखते हैं, लठैतों को रखते हैं और ये लठैत जिस तरह से अत्याचार करते हैं आदिवासियों पर, इन सारी चीजों पर पुनर्विचार किया जायगा ।

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, the report which appeared in the newspapers has thrown some more light which I did not And in the reply of the Minister. It is stated here, the preliminary enquiry made by the police reveal that the bodies were thrown into the river after a group of armed men chased and assaulted upon 250 Adivasi men, women and children, picking up coal and scrap and all that. And the armed men belonged to a contractor. Sir, the question here is not whether such things were happening earlier or not. Is it a comparison that the Janata Party Government wants to make and be satished mat certain things were happening earlier too? Why is it that after declaration after declaration, after assurance after assurance, everyday we are finding these incidents? You would agree that so far as the landlords and contractors are concerned, whether they belonging to the Congress Party or to the Janata Party or to any other party, it is a fact that today they have become more aggressive. How is it that a contractor is allowed to keep a private army of goondas with arms and what was the police doing there? So much additions have been made to the police. Is it only to run after us and find out where somebody is meeting whom? Can't it find out how they could store arms? There is also a report in the police that illegal arms, cartridges, etc. have been found. What was the police doing about it and what has the Government done today to find it out? Have they arrested the contractor? They won't be able to put the things right unless the contractor and the actual fellows who employed those people have been taken into custody. They are set free by law. Just taking recourse to law won't set the things right. Has the Government taken into custody the contractor who has employed the goondas and those armed people who chased 250 tribesmen in that area? If these things go on like this, naturally it is bound to lead to more and more discontentment among the tribals. Discontentment is going to ris$_e$ among the Harijans and the tribal people if they are treated even after 30 years of independence like second-class citizens, if they do not have any independence, if they do not have any democratic rights. In these circumstances how are we going to establish our credence with them? How our assurances are going to help them?

I would like to know from the Minister, what concrete steps—apart from pious assurances that so many persons have been arrested, so many cases have been registered—the Government propose to take to set **the**

[Shri Harkishan Singh Surjeet] matters right and whether they have taken into custody the said contractor and those who employed those armed persons. Only then we will be able to create confidence among them.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मैंने अपनी ओर से कोई तुलना नहीं की और न मैं तुलना करना चाहता हूं । जहां मनुष्य की जान जा रही हो वहां तुलना से हमें कोई सन्तोष प्राप्त नहीं करना है । एक भी यदि ऐसी घटना होती है तो हमारे लिये शर्म और कलंक की बात है और हम उसके लिये दुखी है और हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है । हम कम्पैयर नहीं करते । माननीय सदस्य स्वयं कम्पैयर करते हैं और फिर मुझे उत्तर देना पड़ता है । जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि सरकार क्या कर रही है, बार-बार आश्वासन दे रहे हैं, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो इतनी बड़ी समस्या है इसका एक साल या पन्द्रह महीनों में समाधान होने वाला नहीं है । यह बहुत बड़ी समस्या है और जो बातें कही जा रही हैं उसका जवाब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब ही उसका नहीं है, गोआ कि वह भी है । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई रिसपान्सिबिलिटी नहीं है । मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि पुलिस की कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं है, मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार की रेस्पांसिबिलिटी नहीं है । ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं । कांट्रेक्टर को इस एरिया से जहां तक सम्भव हो हटा देना चाहिए चाहे वह फारेस्ट का कांट्रेक्टर हो, चाहे एक्साइज का कांट्रैक्टर हो चाहे और किसी तरह का कांट्रेक्टर हो । यह भी ठीक है कि पुलिस भी उनके साथ सद्भावना से, सहानुभूति से और संरक्षण के भाव से काम करे । यह भी उतना ही जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर उनका ध्यान जाए और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो ग्रीवांसेज हैं, उन को हल करे । यह भी उतना ही जरूरी है कि उन की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, प्लानिंग से और मजबूत बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, सबल बनाया जाए । और यह भी उतना ही जरूरी है कि जो लोग शोषक हैं उनका हृदय-परिवर्तन हो... (*Interruptions*) ...उसका मन-परिवर्तन हो, यह भी उतना ही जरूरी है...

श्री कल्प नाथ राय : यह क्या शिक्षा दे रहे हैं मन्त्री जी ?

श्री धनिक लाल मंडल : यह काम है, अनेक काम हैं जो...

श्री कल्प नाथ राय: क्या आपने जमशेदपुर के कलक्टर को मोअत्तिल किया है ?

श्री धनिक लाल मंडल : उन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया है और हम उनकी तारीफ कर रहे हैं । इसलिए मैंने जवाब दिया, जहां प्रशासन ने फ्राम्पट काम किया है, वहां पर तुरन्त जाकर एक्शन लेने का काम किया है, हमें चाहिए उसकी तारीफ करें तो (*Interruptions*) ...श्रीमन, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे काम होते हैं वहां हमें उस की तारीफ भी करनी होती है, जहां उस का खराब काम होता है हम को उसकी निंदा भी करनी होती है । ऐसा नहीं होगा महोदय. कि एक स्वर से सब की निंदा की जाए, और फिर हम सोचें कि उसका मोरेल ठीक होगा । मोरेल तभी ठीक हो सकता है, पुलिस का आत्मबल या प्रशासन का आत्मबल उसी हालत में ठीक हो सकता है जब हम उसकी अच्छा काम करने पर तारीफ करें और बुरा काम करें तो निंदा करें । यह नहीं कि सभी कामों में उन की निंदा करें । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने मौके पर जाकर जो भी काम हो सकता, सब किया । माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उन को जानकारी देना चाहता हूं कि आदिवासियों की जीवन दशा सुधारने के लिए हम ने सभ तरह के प्लान बनाए हैं कि जिससे इसपं चवर्षी

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभापति जी, जमशेदपुर में जो घटना घटी है वह वाक्यी में बहुत दुःखद है और हर आदमी की सहानभूति प्राप्त करने लायक है। वहां पर जब मैं गया –चूंकि माननीय राज्य मंत्री ने मेरे नाम का जिक्र किया है– मैंने देखा कि सभी वर्ग के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जो लोग मारे गए हैं, पानी में डुबा

इसके साथ साथ मैं आप को कह रहा हूं कि ड्राइवर एरिया का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस को भी हम डाइरेक्टिव्ह देने जा रहे हैं। हमने एक योजना भी बनायी है और आज तक जिन पावर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ हम उन पावर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप देखेंगे, उस एरिया में जिस तरह से गुण्डागर्दी हो रही है उस को बर्दाश्त नहीं होने देंगे जिस तरह से...

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : : जमशेदपुर की घटना का जवाब आप कहां दे रहे हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : जी हां, जमशेदपुर की घटना के बारे में ही आप को बता रहा था।

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, he has not answered my specific question whether the contractor has been taken into custody or not.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I have said in my original statement that this thing is being looked into. It is being considered.

कर या डूब कर, उन के प्रति सब की सहानभूति थी। जितने भी वर्ग के लोग वहां थे सब के मुह से सुनते थे, मैंने भी तीन-चार घंटे घूमकर देखा है। अब सवाल यह होता है एक तो "टिस्को" का मैनेजमेन्ट है, एक वहां के गरीब आदिवासी हैं। एक कांट्रैक्टर फैक्टर है एक एडमिनिस्ट्रेशन भी फैक्टर है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वहां के लोकल एडमिस्ट्रेशन ने बड़ी तत्परता से काम किया है इस घटना के बारे में।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उस के पहले वेजेज की बात बहुत दिनों से चल रही थी।

श्री भोला पासवान शास्त्री : अभी तो एडमिनिस्ट्रशन का सवाल है। जिस घटना को मैंने देखा वह 16 तारीख को 11 बजे घटी 12.10 पर गोलमुरी पुलिस स्टेशन में खबर पहुंचने पर 12.20 पर वहां के थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे और इतनी तत्परता से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने काम लिया है कि मैं कोशिश कर रहा था कि वहां कहीं लैक्सिटी मिल जाय, लेकिन मैं कुछ नहीं पा सका। मैं कहीं भी लैक्सिटी को पकड़ना चाहता था लेकिन वहां के डी० सी० ने, वहां के एस० पी० ने और थानेदार ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। वह वहां पहुंचे और उन लोगों का घेराव किया और वहां अरेस्ट भी की और उन्होंने तुरन्त गोताखोरो को बुलवाया और दो लाशें उन को उसी स दिन मिलीं। दूसरे दिन जब डी० सी० 17 तारीख को पहुंचे तो फिर उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और फिर पानी को छनवाया। तीन लाशें वहां फिर मिलीं। हम को बतलाया गया कि उन में दो हरिजन हैं, दो आदिवासी है और एक कुरमी भाई है जो साथ साथ रहते हैं। उन में एक है लोखी मुन्डाइन जो पत्नी है जगन्नाथ मुडा की। उस की आयु है 20 वर्ष। दूसरे हैं छोटु महतो जो पुत्र हैं रतन महतो के और

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

उस की आयु है 14 वर्ष की। तीसरे कमला है जो पत्नी है जयसिंह मुडा की, उसकी आयु 18 वर्ष की है। चौथी है सीता, जो पुत्री है सुमरातूरी की उसकी आयु 11 वर्ष की है और पांचवें हैं वीर सिंह रविदास जो पुत्र हैं दशरथ रविदास के और उन की आयु 15 वर्ष की है। इन में जो सीता है उस के माथे पर एक जख्म भी है और बाकी लोगों की तो है पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। इन लोगों को पानी में धकेल दिया गया या डूबा दिया गया और वहां पानी बहुत गहरा था। मैंने स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। मैं अपने से गया था। वहां की डेयरी से जो नाला निकलता है वह सुवर्ण रेखा में जा कर मिलता है और दूर से पानी गिरने के कारण वह बहुत गहरा हो गया था। वहां 12 या 13 फुट पानी था और दलदल था। दूसरे दिन जो लाश निकाली गयी तो वह दलदल में नीचे से निकाली गयी थी और उस के बाद परिवार के लोगों को एक सौ रुपया दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। दूसरे दिन भी जो परिवार के लोग थे उन को लालटेनें दी गयीं डालडा और खाने का चावल दिया गया, जो कपड़ा आदि दिया जाता है वह तुरन्त दिया गया। मैं मानता हूं कि घटना बहुत दुखद है। वह गरीब लोग हैं। एक लड़की तो उस में प्रैगनेंट थी, सीता। मैं उस की मां से मिला था। मैं उस के घर में मिलने के लिए गया था। लालटेन जला कर ले गया था तो उसकी मां कहने लगी कि आप तो लालटेन जला कर लाये हो लेकिन मेरी तो लालटेन बुझा गयी। वह सीता नाम की लड़की के लिए कह रही थी। तो हमें देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की लैक्सिटी कहीं न हो। यह सबसे पहली बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करता है तो उसे कहना चाहिए, मानना चाहिए। एक स्तर से आब्जर्व करना चाहिए। मैं खुद बड़ा क्रिटिक था और चाहता था लैक्सिटी पकड़ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने बहुत तत्परता से काम किया और उन लोगों ने कहा कि हम एहतियात रखेंगे कि फिर दुबारा ऐसा कांड न होने पाये। कमिश्नर से भी मैं मिला कमिश्नर ने भी बहुत काम किया। अच्छे कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि हम उस को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं और टाटा ऐसी जगह है कि जहां हर तरह के इंटरेस्ट के लोग हैं। मेरे दोस्त भीष्म नारायण सिंह जी जानते हैं अच्छी तरह से कि तरह-तरह के एलीमेंट वहां हैं। आज से सात, आठ वर्ष पहले वहां कोई कंट्रैक्ट नहीं था। जो स्लैगडम वहां से निकलता था वह डम्प कर दिया जाता था और वह गरीब मजदूर लोग वहां से वह लोहा बीन कर ले जाते थे बड़ी महंगी चीज 1 P.M. होती थी। उसकी ढुलाई करके कुदाली, बर्तन आदि लोहे के अच्छे बनते थे यही वजह है कि 7-8 वर्ष पहले तक वहां कांट्रेक्ट सिस्टम नहीं था। 7–8 वर्ष से लोग मिलकर इनका कांट्रेक्ट देने लगे। यह एग्रीमेंट दिसम्बर 1978 तक का है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि अभी तो लोग वहां से भाग गए हैं। जो जबरदस्त आदमी थे, सबका नाम लिया गया था। ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी कुर्की कर ली है। जो लोग वहां हैं उन्होंने कहा कि हम लोग उनको पकड़ेंगे। कम से कम जमशेदपुर के बारे में मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन को दोष नहीं दे सकता। कोई मित्र को मालूम हो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में लचर है तो वह कहेंगे तो मैं मान लूंगा। लेकिन जो भी हमको मालूम है, हमको उनकी वकालत नही करनी है, लेकिन जो मैं ने समझा है वह आपके सामने, सदन के सामने जरूर कहना चाहूंगा।

अब कांट्रेक्ट का सवाल है, यह सवाल बड़ा जबरदस्त है क्योंकि छोटा नागपुर का जो बैल्ट है वह अब इंडस्ट्रियल बैल्ट हो रहा है। वहां पर बोकारो है, जमशेदपुर है, रांची है। यह सवाल

कल बोकारो में उठ सकता है, रांची में उठ सकता है। एक तरफ आप जानते हैं कि धन में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर वहां पर गरीब आदमी वर्षों से रह रहे हैं। हम लोग यह महसूस करते थे कि इस तरह आज भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं। उनका जीवन आज भी ऐसा हो रहा है। हम लोग किस मर्ज की दवा हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। यह बात ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कांट्रेक्ट सिस्टम पर विचार करें। टाटा को कहिए। टाटा के आदमी भी आये थे। मोदी साहब कलकत्ता उस दिन चले गए, वह परिचित भी हैं लेकिन टाटा का जो रिप्रजन्टेटिव आया उनसे हमने बड़ी बात की और उनको कहा कि आपका इनडाइरेक्ट इंवाल्वमेंट हो जाता है। आप स्क्रैप का कांट्रेक्ट देते हैं और कांट्रेक्टर अनडियायरेबुल ऐलीमेंट्स को रखकर मनुष्य की हत्या करवाते हैं। पानी में डुबाकर मर्डर किया गया, मारा गया। जो सीता नाम की एक लड़की थी उसकी बहन ने जो बयान दिया वह हम लोग सुनकर हैरान रह गए। उसकी गोद में बच्चा था। काफी वहां गुत्थमगुत्था हुई और उसको नदी में धकेल दिया गया। जिस आदमी की वह वाइफ थी वह मर गई वह उसको भी निकालना चाहता था लेकिन उसने देखा कि वह डूब गए हम भी डब जायेंगे तो वह किनारे हो गया। इसलिए यह सवाल ऐसा है कि जो बिलकुल निर्धन हैं उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं है। मैं कहता हूं कि टाटा की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं है। टाटा के पास अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे लोग हैं। अगर आंध्र में साइक्लोन आया तो वहां पर भी दान दिया, बिहार में भी रिलीफ के लिए दान देता है, उसकी पब्लिसिटी है लेकिन उसकी बगल में ऐसा कांड हुआ। उसको कहते हैं—दिया तले अंधेरा। टाटा के जो आदमी हमसे मिले उन्होंने कहा कि हमने समझा था कि दो कांट्रेक्टर्स का झगड़ा है। कांट्रेक्टर्स वहां पर पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं। लठैत रखते हैं। उनको दबाने के लिए। तो पांच आदमी डूबकर मर गए। हमने कहा कि आपका वैल्फेयर डिपार्टमेंट है, आप जाकर उनके परिवार के साथ मिलते, उनको सहानुभति हुई होती। एक सगुन होता है तकलीफ में वहा लोग थे। लेकिन जब हम वह गए तो उनको खुशी हुई कि हमारा देखने वाला दुनिया में है, कुछ लोग जो आ जाते हैं हम लोगों को कन्सोल करने के लिए। यह भवना उनकी थी, बड़ा सन्तोष हुआ और तमाम इलाके में हम लोग गये। आखिर हम लोग बच्चों को बचा नहीं सकते थे लेकिन मनुष्यता के नाते, अपने देश के नागरिक के नाते हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को हक है ऐसे वक्त में जाकर देख सकता था कि हमारे देश में क्या घटना घट रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके कांट्रेक्ट को कैंसिल करे और उनको कांट्रेक्ट नहीं दे। जैसी पहले थी, ओरिजनल पोजीशन के ऊपर लाये। उन्होंने कहा ऐसा करेंगे तो ला एक्ड आर्डर का सवाल उठेगा। तो ऐडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। लेकिन जिनको वह लोहा चुनने नहीं दिया गया, जिनका लीगल राइट उनको नहीं था लेकिन चुनते थे कांट्रेक्टर के

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

आदमी को कुछ पैसा दे दिया तो चुनने दिया, नहीं तो नहीं चुनने दिया । पहले भी इसको लेकर झगड़े हुए जैसे भीष्यम नारायण सिंह जी कहते हैं, पहले भी झगड़ा हुआ लेकिन हालत यह है कि हमारे देश की सरकार, चाहे केन्द्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, जब आखिरी नौबत आ जाती है तब सरकार के कान खड़े होते हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यही मेरा कहना है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह मैं कह रहा हूं । पहले तो मैंने ही यह बात कही है । सरकार यह काम करती है कि आखिरी समय पर जब किसी की जान चली जाती है तब सरकार बड़बड़ाने लगती है । ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की कि यह जो दुर्घटनायें हरिजनों पर हो रही हैं उनको रोका जा सकें । वैसे आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, हरिजनों की सुरक्षा के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है । वह मजिस्ट्रेट को पावर दे सकती है कि अगर कोई बैड करैक्टर, एन्टी सोशल एलीमेंट आदिवासियों को सताता है . . .

श्री भीष्म नारायण सिंह : उसको बंद करे ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं मंडल साहब को जानता हूं । जो मैंने समझा है वह मैं कह रहा हूं । जो मैंने फालो किया है वह मैं ने बता दिया । अगर मैं गलती पर हूं तो वह समझा देंगे ।

श्री धनिक लाल मंडल : वह तो वही समझेंगे जो उनके मन में है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आज गरीब लोगों का सताया जाता है, परेशान किया जाता है । कृषक जो खेत में पैदा करता है वह उसमें से काट कर ले जाता है और जो बचा-खुचा होता है वह चुनकर वह गरीब अपने यहां ले जाता है उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कंटरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्दी-जल्दी बढ रही है तब सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, राज्य सरकार को देखना चाहिए कि इसका असर गरीब लोगों पर क्या पड़ रहा है । इससे उसके जीवन पर क्या बीत रहा है । इसमें उनकी इकोनोमिक लाइफ को, सोशल लाइफ को देखना चाहिए । मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहने के लिए मजबूर हूं कि जमशदपुर, घटिया, बोकारो, छोटा नागपुर में ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । कम से कम आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए आपको कुछ न कुछ करना चाहिए । उन के लिए मुश्किल हो रहा है वह कहां जाएं । आज वे लोग शहर की तरफ भागे आ रहे हैं ।उनके लिए देहातों में रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं है इसलिए उनको शहर में आना पड़ता है । मैं चाहुंगा कि सरकार को इस बारे में बेसिकली सोचना चाहिए देखना चाहिए । मैं गवर्नमेंट को सजैस्ट करूंगा कि वह ऐसा पहलू देखें ताकि कम से कम गरीब लोगों की जान न जान पावे । उसको भी जीने का हक है । उनको खामखांह पकड़ कर मार दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है । आदमियों को ऐसा करते हुए पकड़ा गया है । मैंने शरू से में भी कहा था कि टाटा का जहां तक सवाल है उसमें एडमिनिस्ट्रशन लचर रहा है । मैं ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत की है । उन्होंने हम से कहा कि हम इसको ठीक से देखेंगे, कड़ाई से देखेंगे हम छोड़न वाले नहीं हैं । हम चाहते हैं कि जमशेदपुर जैसी घटनायें दुबारा न घटने पायें ।

माननीय मंत्री जी ने क्योंकि मेरा नाम लिया था इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वरना मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं भी वहां गया था। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जमशेदपुर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लचर है। मैं इतना कहूंगा कि इस घटना के बारे में फिजिकल प्रोंप्ट एक्शन हो सकता है। यहां पर यह कहा गया कि 20–25 आदमी मारे गए। मैं यह कहूंगा कि जो मरे हैं उनका पता नहीं लग रहा है। उनके परिवार वाले परेशान हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा है और सब से कहता हूं कि जिसको भी इसका क्लू मालूम हो वह हमारे सामने रखे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताए। कम से कम हम को जानकारी तो होगी। उन के परिवार वालों को कुछ राहत तो मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने पांच हजार रुपए का एलान किया है। कम से कम उनको इससे कुछ राहत तो मिले गी। मुख्य मंत्री ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली है और डी० सी० और टाटा मैनजमेंट के लोग भी वहां गए हैं। सरकार ने कहा है कि पांच पांच हजार रूपए देंगे और सितम्बर 3 या 4 तारीख तक उनको पेमेंट हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि रुपया देना इस समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन एडमिनिट्रेशन या समाज इस बारे में जो कुछ कर सकता है उसने किया हैं। किसी जान की कीमत पांच हजार रुपए नहीं है। समाज में हरिजनों की जो वैल्यू है उसके मुताबिक उनको रुपए भी दिए गए हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक बुढ़िया थी उसकी 12 वर्ष की एक लड़की थी जो वहां पर काम करती थी और लोहे के टुकड़े चुनती थी। उसके मर जाने से उसका कोई सहारा नहीं रहा। इस प्रकार की दूसरी घटनायें भी हो सकती हैं। इसलिए मैंने कहा कि रुपया देने से जान की कीमत अदा नहीं हो जाती है। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हरिजनों और आदिवासियों की तरफ विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको थोड़ा सा पैसा देकर छोड़ दिया जाय।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): म यह जानना चाहता हूँ कि वह ठेकेदार गिरफ्तार हुआ या नहीं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : वह ठेकेदार गिरफ्तार हुआ है। हमारे पास कुछ नोट लिखे हुए हैं। मेरा कहना यह है कि आगे के लिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हों।

श्री इन्द्रदीप सिंह (बिहार) : मैं माननीय शास्त्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं...

श्री उपसभापति : पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हू...

श्री कल्प नाथ राय : जमशेदपुर का यह ठेकेदार कहां का रहने वाला है और इसका नाम क्या है ?

श्री धनिक लाल मंडल : इस ठेकेदार का नाम शिव सिंह है।

श्री कल्प नाथ राय : वह कहां का रहने वाला है।

श्री धनिक लाल मंडल : होगा कहीं का ?

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : वह तो बेनामी ठेकेदार था।

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन्, मंत्री जी किस तरह से जवाब दे रहे हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मैं सदन में बोल रहा हू। आपने मुझे बोलने के लिए कहा है और हमारा अधिकार भी उन

[श्री धनिक लाल मंडल]

लोगों से कम नहीं है । शास्त्री जी ने जो बात कही है वही बात मैंने भी कही है । जब पिछली बार मैं इन क्षेत्रों अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने गया था तो मैंने देखा कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े शहर तो बन गए हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है । रांची, राउरकेला, बोकारो आदि बड़े बड़े शहर इन क्षेत्रों में में बन चुके हैं । इनके बारे में मैं ने कहा था कि ये गरीबी के दल दल में भोग के टापू हैं । इतने विकास के बावजूद वहां पर गरीबी छाई हुई है । आदिवासियों की जमीन ले ली गई, लेकिन उनका कोई विकास नहीं हुआ । वहां पर बड़े बड़े नगर जैसे रांची, राउरकेला, बोकारो, टाटानगर आदि बन गए, लेकिन आप शहर से दूर चले जाइये तो आपको वही टूटी-फूटी सड़कें मलेंगी और कहीं कहीं तो सड़कें भी नहीं हैं । पीने का पानी के कोई प्रबन्ध नहीं है, स्कूलों का कोई प्रबंध नहीं है । स्वास्थ्य सेवाओं का कोई प्रबंध नहीं है । वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है । अगर मैं यह कहूं कि वहां पर हालत और भी खराब हुई है तो यह गलत न होगा । इसीलिए मैंने यह कहा है कि ये शहर इन क्षेत्रों में भोग के टापू हैं । इन लोगों को गरीबी के दल दल में से निकालने का हम लोगों ने अब प्रयास किया है । शास्त्री जी जानते हैं, हमने एक स्पेशियल एरिया प्लान बनाया है ।

आप को जरूरत नहीं है, आप जो जोर से कह रहे हैं । मैं आपसे भड़कना नहीं चाहता । ऐसी बात नहीं है । ऐसे आप मत कीजिए । हम बहुत दिनों तक साथ साथ काम कर चुके हैं । इसलिए आप मन में यह मत लीजिए इसमें भड़कने का कोई प्रश्न नहीं है । वही मैं कह रहा हूं मेरी तरफ से ऐसे मत लीजिये । मैंने इतना ही कहा है कि हम लोगों को खुद इसका अहसास है । यह बहुत ही दुःखद चीज हुई है खासकर के आदिवासी क्षेत्र में जहां पर कि नये कारखाने लगे हैं चाहे वह बोकारो का कारखाना हो । खैर और तो पुराने कारखाने हैं । राऊरकेला और बोकारो के बारे में बतलाना चाहता हूं कि वहां के जो लोग हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ है । हमारी जो ट्राईबल सब प्लान है उसमें हमने प्रोग्राम रखे हैं उस प्रोग्राम का नाम है 'ए स्पेशल एरिया प्लानिंग'। इस प्रोग्राम के तहत हमने यह कहा है कि ऐसे जो शहर हैं जिसमें लोगों के जीवन को डिसप्लेस किया है, आदिवासी डिसप्लेस हुए हैं उनकी जमीन गई है, उनको फिर से रिहेबिलिटेट करने के लिए जो शहरी आवश्यकताएं हैं जैसे पोलटरी, मिल्क, वेजीटेबल, फ्रूट्स की आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध की जाएं । आदिवासियों की जो रुचि है वह खेती का काम करने में है। तो हम लोगों ने कहा कि स्पेशल एरिया प्लानिंग में टाऊन के 10 किलोमीटर के रेडियस में स्पेशल एरिया प्लानिंग करके वहां के लोगों को शहर से, इंडस्ट्री से जोड़ना चाहिए। जो शहरों की आवश्यकताएं है, इंडस्ट्री की आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप वहां पर चीजें बनाई जाएं और उनको उसमें लगाया जाए तभी उनका जीवन सुधरेगा । जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी ओर हमारा ध्यान गया है । इसलिए मैं शास्त्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों इस पर काम कर रहे हैं । केन्द्र सरकार तो अपना अनुदान दे रही है । स्पेशल ऐड. . . .

श्री कल्प नाथ राय : ठेकेदारों के बारे में कुछ. . .

श्री धनिक लाल मंडल : ठेकेदारी के बारे में बाद में कहूंगा । अभी तो स्पेशल एरिया प्लानिंग के बारे में बता रहा हूं । इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं चाहे प्राईवेट सेक्टर की हों या पब्लिक सेक्टर की हों उनका

भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए । स्पेशल एरिया प्लानिंग में इन लोगों को बसाने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए उनका भी काम होना चाहिए ।

श्री नत्थी सिंह : ठेकेदारों को... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : फिर चर्चा करेंगे । सदन की कार्यवाही सवा दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at nineteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman (Shri Arvind Ganesh Kulkarni): in the Chair.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष जी, 16 अगस्त को जमशेदपुर में जो घटना हुई जिसमें आदिवासी महिलाओं और बच्चों को खदेड़ कर डुबा दिया गया, यह बड़ी दर्दनाक घटना है, इस का भी चित्रण यहां हो चुका है । छोटा नागपुर डिवीजन में ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Jha, you ask for only clarifications.

विवरण हो गये हैं अब आप बेशक 2-3 क्लैरीफीकेशन पूछो ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा बशर्ते कि आप आश्वासन देंगे कि ऐसा दूसरे लोग भी करेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी): चलिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : क्योंकि दूसरे लोगों के वक्त मैं देखता हूं कि मौका छोड़ दिया जाता है जितनी बैकग्राउंड या मेटीरियल देना हो मैं आपकी बात से सहमत हूं । मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि बिल्कुल टु दी प्वाइंट सवाल किया जाय ।

THE VICE-CHAIRMAN **(SHRI ARVIND GANESH KULKARNI)**: We have to start discipline at home. So you should start it yourself. Go ahead.

श्री शिव चन्द्र झा : तो अब यह जो घटना हुई, इसके पीछे 2-3-4 फैक्टर्स हैं, बातें हैं, मंत्री महोदय ने कहा कि सब मिलजुल कर हम लोग उसका निराकरण करें, इसको निपटायें, यह ठीक है । लेकिन कुछ बातें हैं जो अकेले भी वह दल जो सरकार में हैं वह कर सकता है, सबको बुला दें नियंत्रण दें, इसकी जरूरत नहीं है । सत्ताधारी सरकार खुद सक्षम हो सकती है करने में । सारी जो परिस्थिति है उसमें पहली बात, टिस्को-टाटा कम्पनी जो एक प्राईवेट कम्पनी है, वह बात जैसी है लेकिन जिस रूप में उसका विकास हुआ है और जो आक्टोपस के रूप में हैं उसका जाल फैल गया है, वह एक शोषण का केन्द्र हो गया है ।

मंत्री महोदय ने शायद कहा "भोग का टापू" हो गया है । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एक प्रांइवेट कम्पनी है । यह एक बुनियादी बात, एक ऐसी समस्या है जो वहां है । उसको समझ लें और एकरैडिकल सलूशन के लिये यह जरूरी है ।

दूसरी बात जो ट्राइबल पीपल है, जो आदिवासी लोग हैं, वे बहुत दिनों से सताये गये हैं । इसमें कोई दो मत नहीं हैं । उनके लिये मंत्री महोदय ने कहा कि स्पेशल एरिया प्लैनिंग और साथ-साथ आगामी योजना के लिए जो तीन हजार की बात की, बहुत अच्छी बात है, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बात है जो फुल एम्पलायमैंट के लिये सिर्फ इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जय प्रकाश कमेटी बनी थी आन्दोलन से बहुत पहले, उसमें सुचेता जी भी थी और

[श्री शिव चन्द्र झा]

अनएम्पलायमैन्ट को दूर करने के लिये, फुल एम्पलायमैन्ट करने के लिये, आदिवासियों का ही इलाका पिक-अप किया गया कि यहां पर फुल एम्पलायमैन्ट की पालिसी चलाई जाए ।

तीसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि कान्ट्रैक्ट लेबर खत्म हो, बन्धुवा मजदूर की व्यवस्था खत्म हो । वह व्यवस्था बहुत खतरनाक है । वह सिलसिला चल ही रहा है । इसको खत्म करना जरूरी है । कन्ट्रैक्टर जो मजदूर को बहाल करता है, मजदूरी कम देता है । वह बात वहां भी है । अगल-बगल में दो रुपया रोज कमाते हैं, लेकिन जो कान्ट्रैक्टर वहां जो डम्प करता है स्टील कम्पनी का, वह एक रुपया देता है । तो यह बैकग्राउण्डस हैं जिनको ठीक से टैकल करने पर हम ऐसी परिस्थितियों को हमेशा के लिये बन्द कर देंगे और इनका अन्त कर देंगे ।

इसलिए मंत्री महोदय से मेरा सवाल है कि जो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी है, जो भोग का टापू आपने कहा, जो शोषण का एक बहुत बड़ा अड्डा है, और जिस के पंख फैल गये हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पर हैं और जगह भी है, जिनकी वजह से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं क्या सरकार टाटा आयरन खण्ड स्टील कम्पनी का नैशनलाइज करेगी ? आप बात उठाएं कि इसकी एक व्यक्ति के मार्फत मिल्कियत लेना ठीक नहीं है । इसका स्वामित्व समाज का हो । अब जो आदिवासी वहां डूबे हैं, जो वहां मारे गये हैं, सरकार उन के परिवारों को उचित कम्पैनसैशन देगी कि नहीं ? उन लोगों को उचित मुआवजा मिले । क्षति हो जाने पर आप रेल में देते हैं, दूसरी जगह देते हैं । इसीलिये उन को भी उचित मुआवजा मिले । ऐसा सरकार करेगी या नहीं ?

कान्ट्रैक्ट लेबर का जो सिलसिला है इसको स्ट्रिक्टली आप अबालिश करें । जहां खत्म हो रहा है, ठीक है । आदिवासियों के साथ स्ट्रिक्टली कान्ट्रैक्ट लैबर की बात न चले । यह आप बन्द करने जा रहे हैं कि नहीं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : समाप्त कीजिये ।

श्री शिव चन्द्र झा : इस के साथ ही आपने कहा कि स्पेशल एरिया प्लैनिंग फुल एम्पलायमैन्ट की नीति, स्पेशल एरिया प्लैनिंग में तीन हजार की लागत लगा कर जो फुल एम्पलायमैंट की बात ... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Minister, please reply.

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, सभी रोगों का इलाज राष्ट्रीयकरण ही नहीं है । दुनिया में जितने भी रोग हैं उसका मास्टर इलाज राष्ट्रीयकरण जो माननीय सदस्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक टाटा कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है यह सरकार के विचार में नहीं है । महोदय जो कान्ट्रैक्ट लेबर है, माननीय सदस्य का कहना बिलकुल दुरुस्त है कि टाटा कम्पनी में कुछ ऐसे काम हैं जो ठेकेदारी प्रथा से लिये जाते हैं और ठेकेदार लोगों को लगा कर उन से काम लेते हैं और उन को ठीक मजदूरी नहीं मिलती है । जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है, यह बात सही है और जरूर

इस पर विचार करेंगे कि कानून का सख्ती से पालन किया जाए और जहां तक सम्भव हो ठेकेदारी-प्रथा को खत्म किया जाए। जैसा मैंने अपने मूल बयान में कहा है कि जो मजदूर हैं उन को वाजिब मजदूरी मिले यह सही है और जहां तक सब को काम देने की बात है स्पेशली एरिया प्लैनिंग और दूसरे जो प्लैनिंग हैं, उसमें काम देने की बात है । इसीलिये तो प्लैनिंग होता है । इस बात को ध्यान में रख कर कि जो भी काम करने लायक आदमी हैं उन को काम मिले और उसकी जरूर कोशिश की जायगी . . . (*Interruptions*) . . . कंपेन्सेशन के बारे में मैंने अपने मूल बयान में कहा है, आप उस को पढ़ लें । एक्स-ग्रेशिया कंसेशन कह लीजिए या रिलीफ कह लीजिए, 5000 रु० देने का ऐलान किया है, बिहार के मंत्री ने प्रत्येक परिवार को, जिस के आदमी मर गए हैं, वह देने का ऐलान किया है. . .

श्री शिव चन्द्र झा : 10,000 रु० तक का ?

श्री धनिक लाल मंडल : यह आप का सुझाव है ।

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में ठेकेदारों के जरिए, उन के गुण्डों द्वारा मजदूरों पर जो जघन्य जुल्म किया गया है उस संबंध में सफाई देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हमारे मुख्य मंत्री . . .

THE VICE CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You please ask Questions.

श्री भोला प्रसाद : वही मैं पूछ रहा हूं । तो मुख्य मंत्री गरीब वर्ग से आए हैं और इसलिए वह हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म के खिलाफ संरक्षण देने के लिए मुस्तैदी से कदम उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ठेकेदार का लठैत जिस ने मजदूरों को, आदिवासी मजदूरों को, डुबा कर मारा या वह गरीब का बेटा है ? तो गरीब का बेटा होने से वह गरीबों का संरक्षक नहीं हो जाता है । अगर वह ठेकेदारों का, पूंजीपति का लठैत है । इसी तरह से, कर्पूरी ठाकुर गरीब परिवार से आए हैं इसलिए वह अमीरों की तरफदारी नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है । दूसरी तरफ वे अगर मुस्तैदी से कदम उठा रहे हैं तो वह भी इस बात से देखा जाएगा कि जो भी कदम वे उठा रहे हैं उसमें हरिजनों और आदिवासियों के खिलाफ इस तरह के जुल्म की, हत्याकाण्ड की घटनाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं ? लेकिन नतीजा यह बताया है मिसाल यह है, एक के बाद एक— बेलछी के बाद विश्रामपुर, धरमपुर और फिर जमशेदपुर--इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं और इस तरह के जुल्म बढ़ते जाते हैं। तो क्या यह मुस्तैदी की पहचान है या जुल्म करने वालों के प्रति यह दया का बर्ताव है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : ठीक है । जल्दी समाप्त कीजिए । आप सफाई दे रहे हैं।

श्री भोला प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह चार्ज है कि, चाहे अब तक जो कुछ भी कहा जा चुका है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जुल्म करने वालों को सरकार के पुलिस अधिकारियों की ओर से संरक्षण दिया जाता है और तथ्यों पर पर्दा डाला जाता है जिस वजह से ये जुल्म बढ़ रहे हैं।

अब मैं घटना के संबंध में एक-दो बात जानना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं । पहली बात यह है कि कहा गया है कि जब जमशेदपुर में इस तरह की घटना हुई तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बहुत ही तत्परता से कदम उठ या अगर तत्परता से कदम उठाया गया है तो अभी तक वह जो ठेकेदार है, वह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है ? ठेकेदार को गिरफ्तार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाया गया है ? क्या यह सच है कि वह ठेकेदार ट टा का ठेकेदार है, टिस्को का ठेकेदार है और इसलिए टिस्को और टाटा की तरफ से संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए न ठेकेदार के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है और न टाटा ने, जिस ने संरक्षण दिया है, उसके खिलाफ सरकार ने कदम उठाया है । तो क्या यह नहीं बताता है कि यह सरकार, असली जो अपराधी है, ठेकेदार और टाटा कंपनी है, उसके खिलाफ कदम नहीं उठाती है । तो मैं जानना चाहता हूं उसके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

अंत में मैं यह जानना चाहता हूं कि उस इलाके में, जो छोटा नागपुर इलाका है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वह आदिवासी इलाके हैं और ठेकेदारों के जरिए पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर मजदूरों को इस्तेमाल किया जाता है और उन को न केवल मजदूरी कम मिलती है बल्कि उन के ऊपर इस तरह के जुल्म ढाये जाते हैं । तो क्या सरकार यह नीति अमल में लाएगी कि ठेकेदारों के जरिए, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वह काम नहीं लिया जाएगा, खुद डिपार्टमेंट के जरिए और कंपनी के जरिए काम लिया जाएगा । जब तक वह नहीं होता है, मजदूरों को पूरी मजदूरी और पूरा हक दिलाने की क्या कोई गारण्टी की जाएगी ?

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मैंने श्री कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निवेदन किया था, एक तो संरक्षण देने की बात है, पैट्रन बनने की बात है, पैट्रन बन कर संरक्षण देने की बात है और दूसरे, जैसा कहा जा रहा न जैसा गांधी जी कहते थे, खुद बनने की बात है, यानी जिस को संरक्षण देना है उस को कुर्सी पर बिठा कर खुद सलाहकार बनने की बात है । तो मेरा कहना है कि दूसरा रास्ता गरीबों को उठाने के लिये, उनकी भलाई के लिये एक अच्छा रास्ता है और बहुत उपयक्त रास्ता है । बजाय इस के कि हम उनको संरक्षण देने जायें हम उन को ही गद्दी पर बिठा दें और खुद उन के सलाहकार बन जायं, तो यह ज्यादा अच्छा रास्ता होगा मेरी समझ में और इसी लिये मैंने कहा कि हम प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, हम जनतंत्र की दुहाई देते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं तो हम को चाहिए कि उस गरीब को लायक जगह पर बिठ दें और उस को पीछे से सहारा देते रहें त उस से उस की समस्या आसानी से हल ह जायगी इतना ही मेरा कहना था । पैट्र तो लोग बनना चाहते हैं लेकिन उन के सलाह कार नहीं बनना चाहते । खुद नहीं बनन चाहते गांधी जी की तरह से । दूसरे, मैं कहन चाहता हूं कि किसी काम का नतीजा ए दिन में नहीं आता है । आज बिहार क सरकार तत्परता से काम कर रही है

यह बात इस से नहीं कट सकती कि बेलची में, विश्रामपुर में, जमशेदपुर में या धमपुरा में क्या हुआ । सरकार को तो इन कांडों में मौके पर जा कर तत्परता से काम करना है और जो कसूरवार लोग हैं उन को सजा दिलाना है और वह सारा काम समय से होगा । अगर यह काम होगा तो उस का लाजमी तौर पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो अपराधी हैं वे समझेंगे कि उन के अपराध अब कंडोन होने वाले नहीं हैं । तो ऐसी स्थिति में उस का प्रभाव पड़ने ही वाला है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : वह पूछते हैं कि आप ने उन लोगों को अरेस्ट किया है या नहीं ?

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने अपने ओरिजनल ब्यान में कहा है कि. . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You give answer to his specific points.

श्री धनिक लाल मंडल : 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है । जैसा सदस्य महोदय नाम से जानना चाहते हैं, शिवजी सिंह, वह गिरफ्तार नहीं हुआ है लेकिन उस के विरुद्ध प्रोसेस हो रहा है मामला और उस की कुर्की और जब्ती कर ली गयी है और टाटा नहीं उस से भी बड़ी हस्ती अगर उस को संरक्षण देगी तो भी उस को गिरफ्तार किया जायेगा और उस को सजा दिलायी जायगी ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) : मान्यवर,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You have got only two minutes.

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : आप ने समय की सीमा बांध दी है लेकिन यह एक बड़ा अहम सवाल है । मैं दो, तीन, चार, पांच सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । हम लोग जमशेदपुर में जहां पर कि यह घटना हुई बाबूडीह वहां श्री प्रकाश मेहरोत्रा जी के साथ 20 तारीख को गये थे और उस दिन शास्त्री जी भी हमारे साथ थे और हम लोगों ने वहां जा कर निरीक्षण किया और सब कुछ देखा । उसे देखने के बाद श्रीमन् मैं इतना ही कहना चाहता कि दूसरे जलयांवाला बाग की घटना वहां हुई है । वहां का जो दृश्य है उसे मैं सदन में बताना चाहता हूं । हमारे साथ हमारे मित्र मेहरोत्रा जी भी थे । एक तरफ स्लैगडम का पहाड़ है और दूसरी तरफ भी स्लैगडम का पहाड़ है और बीच में सुवर्णरेखा नदी मिलती है उस नाले से । वहां पर उन लोगों को कार्नर कर ले जाया गया । वह जानते थे कि उन को कार्नर किये जाने पर वे उधर जायेंगे और आदिवासी जानते थे कि उधर जा कर हम जंगल में छिप जायेंगे, लेकिन उन को चेज कर के, जानबूझ कर उधर ले जाया गया और वहां जो लोग भी हम लोगों को मिले उन्होंने बताया कि उन का पहले से मारने का प्लान था । जहां स्लैगडम का पहाड़ है उस के एक तरफ रास्ता है । वह जानते थे कि जब उन को चेज किया जायगा तो बाध्य हो कर वे उधर जायेंगे और ऐसी हालत में उन को चेज किया जा रहा था । शास्त्री जी भी हमारे साथ गये थे । पांच छः सौ आदमी वहां इकट्ठे हुए थे और उन्होंने बयान दिया । इस तरह की घटना जो दयनीय हैं, जिस तरह से बर्बरता के साथ उनके साथ अत्याचार किया गया यह दूसरा जलियांवाला बाग था । हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 30 साल पहले भी हरिजन मारे जाते थे । इस प्रश्न में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस मैगनैमिटी में हरिजनों पर अट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, पहले भी होती थीं क्या? लेकिन जैसी विश्रामपुर की घटना, धर्मपुरा की घटना और बेलछी की घटना लोगों को जिन्दा जला डालने की और उन के परिवार वालों के सामने गोली से उड़ा देने की हुई है उनकी मिसाल पहले नहीं मिलती । जमशेदपुर में उनको मारकर नदी

[श्री महेन्द्र मोहन मिश्र]

में फेंकना, इस तरह की घटना माननीय मंत्री जी, इस तरह की लगातार घटनायें जो हो रही हैं उनका उदाहरण नहीं दे सकते। प्रश्न सदन के सामने यह है कि इस बारे में दो मत नहीं हैं कि जनता पार्टी को यह विश्वास है कि हमारे पिछले चुनाव में हरिजनों और आदिवासियों ने वोट नहीं दिये, इसलिए उनके ऊपर उनको ममता नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इन घटनाओं का जवाब देते हुए पहले इस सदन में बताया था कि कि हम एस० पी० और जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी की घटनाओं पर आप क्यों नहीं फिक्स करते हैं? हमारे माननीय शास्त्री जी ने भी क्लीन चिट दे दी और आपने भी कहा कि हमारी पुलिस ने बहुत सतर्कता से काम किया। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे लम्बा इतिहास है। रामा नाम का एक आदमी था। इन ठेकेदारों ने उसे मारकर बोरी में रखकर फेंक दिया। वर्षों की कहानी चली आ रही है। ठेकेदारी की प्रथा शुरू होने से ठेकेदारों और आदिवासियों के बीच में वर्षों से झगड़ा चल रहा हैं। हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेती इन बातों से वाकिफ नहीं थी कि उनके बीच में तनाव चल रहा है? अफसरों के दो घंटे बाद कुछ रिलीफ भेज दिया इसलिए बहुत सतर्क हो गई। लेकिन वह जानती थीं कि आदिवासियों और ठेकेदारों के बीच में वर्षों से झगड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोकल पुलिस और मजिस्ट्रेसी ने कुछ नहीं किया। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि जिले की पुलिस और मजिस्ट्रेसी का एक ही उद्देश्य है कि मैनेजमेंट की गुड बुक्स में रहे क्योंकि उनके बच्चे कल का वहां पढ़ेंगे तो टाटा में नौकरी मिल जाएगी। ...

(*Interruptions*)

दूसरा सवाल श्रीमन्, उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या 5 है। वहां लोगों के मरने की संख्या 8 है। महेन्द्र मुण्डा और सीबू ने चार लाशें वहां निकालीं। एक पीठ पर बच्चा जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि दो औरतें और दो मर्द हैं। एक मैनो मुण्डा ने 11 साल के एक बच्चे को निकाला। महेश्वर यादव ने एक निकाला। इस तरह 8 लाशों की कहानी है। मान्यवर, 25 आदमी उस ओर भागे यह साबित हो गया। लेकिन जब 25 भागे तो उसमें से 5 हो आपके हिसाब से निकले। 20 व्यक्तियों का क्या हिसाब है? इसलिए मान्यवर, यह तभी पता लग सकता है कि जब कि आप जुडिशल इन्क्वायरी करायें। तभी इसका इजहार होगा कि कितने आदमी वहां मारे गये। तभी इस बात का निष्कर्ष निकल सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : मिश्रा साहब अभी मैंने 5 मिनट आपको दे दिये। समाप्त कीजिए।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : श्रीमन, समाप्त कर रहा हूं। श्रीमन, दूसरा मेरा सवाल यह है कि यह वर्षों की जमींदारी प्रथा टाटा की खत्म की जाए। जब हमारी सरकार थी तो विधेयक बनाया, वह पास किया। वह अपील में सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। संविधान में संशोधन हो गया। अगर हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि आप गरीबों के वफादार हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील लम्बित है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें ताकि उनकी जमीन के ऊपर जो आपने महल बनाया उसको बचायें।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : आपको कोआपरेट करना पड़ेगा।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, बिहार सरकार की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया। शेड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स कमीशन जो था उसके चेयरमैन की बातों का भी मैंने हवाला दिया है। इन सारी बातों का

मैंने इजहार किया है । इस सब के बाद कुछ कहने के लिये रह नहीं जाता है मृतक के संबन्ध में, मैंने यह भी कहा है कि स्थानीय अधिकारी ने यह अपील की है कि अगर किसी के पास कोई सुराग हो या किसी के गाय की, लापता की जानकारी हो तो वह नाम दे दें । इसकी जरूर तहकीकात की जाएगी लेकिन अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं आया है; कोई सुराग नहीं मिला है । बिहार सरकार की रिपोर्ट को छोड़ें । खुद जो कमीशन के चेयरमैन हैं और इस के माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी बयान दिया है । इन सब के बाद मेरे पास कुछ कहने के लिये रह नहीं जाता ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : मैंने चार-पांच प्रश्न पूछने हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : आप सिर्फ दो मिनट लीजिए ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : एक-दो मिनट तो आप ही ले लेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You ask straight questions.

SHRI PRAKASH MEHROTRA: I am asking straight questions, Sir.

मैं और मिश्रा जी दोनों वहां गये थे । वहां यह जानकारी हासिल की है कि पांच नहीं आठ लाशें निकाली गई हैं और कम से कम 12, 14 आदमी ऐसे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है वे कहां हैं तो क्या सरकार इसकी जानकारी करा कर, फेस आउट करके वहां के लोगों की शंका का समाधान करेंगी । वहां के लोगों को यह शंका है कि कम से कम 15–16 आदमी मरे हैं ।

दूसरा प्रश्न यह है कि बड़ी अजीब बात है कि टिस्को का जो स्क्रैप है टिस्को की जमीन पर फैला दिया जाता है । उस पर टिस्को का नियन्त्रण नहीं है । वहां पर न तो टिस्को के सुरक्षा के लोग हैं और न ही सरकार की कोई सेक्योरिटी है । जो गुंडा तत्व हैं उन्हीं के हाथों में सब व्यवस्था है । मान्यवर, क्या सरकार यह कदम उठायेगी कि वहां सुरक्षा व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां के जो आदिवासी हैं वे कम से कम तीन पुश्तों से काम करते आ रहे हैं । वहां के स्क्रैप में से लोहा, पीतल, तांबा के जो टुकड़े हैं उनको बेच कर अपनी जीविका कमाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको कोई मिनिमम वेज मिलना चाहिये । या तो इस काम को टिस्को करे और अगर वह नहीं करती तो जो लेबर डिपार्टमेंट है वह ऐसी व्यवस्था करे कि कम से कम उनको 3 रुपये या 4 रुपये वेज मिल जाए ।

तीसरी बात यह है कि वह जो जमीन थी वह सब आदिवासियों की जमीन थी । वे जंगल काट कर अपनी खेती करते थे लेकिन अब वह टाटा की जमीन से मिल गई है । इस प्रकार से उनकी जमींदारी खत्म हो गई है और टाटा की जमींदारी अभी भी चल रही है । इस सम्बन्ध में कुछ कानून पिछली सरकार ने बनाए थे । सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर भी ले लिया था । यह सब होने ही जा रहा था कि इस बीच सरकार बदल गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जो जमींदारी टाटा वालों की है उसको खत्म किया जाए जिससे कि वहां के आदिवासी लोग, जिनको जीवनोपयोगी के लिये कुछ नहीं है, उनको जमीन मिल सके । वे अपनी खेती करके अपना गुजारा कर सकें ।

चौथी बात यह है कि जो कांट्रैक्टर है क्या उसके कांट्रैक्ट को खत्म करेंगे । मान्यवर, जमशेदपुर में हाल यह है कि वहां गुण्डों का राज्य है ।

They are mightier than the mightiest Government.

अगर तो सरकार के पास बिल है इन्फोर्स करने के लिये, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि वहां सैट आफ इम्पोटेंस बैठे हुए हैं जो इसको करना नहीं चाहते हैं, तो क्या कोई

[श्री प्रकाश महरोत्रा]

ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ला एण्ड आर्डर ठीक हो ।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमन्, मृतकों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कहा, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई किसी प्रकार का नाम देता है, सुराग देता है तो जरूर उसकी छानबीन करायेंगे । जरूर इसको आइडेंडीफाई करायेंगे । उससे निष्कर्ष निकालें । इसमें कोई छि की बात नहीं है ।

श्री जीव नारायण सिंह : सुप्रीम कोर्ट. . .

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने आपसे निवेदन किया कि आप से, जनता से या देश से कोई बात छिपाने की नहीं है । सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला न्यायाधीन है उसके लिये हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री जीव नारायण सिंह : उस पर जल्दी कार्रवाई करने के लिये कह सकते हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने यह कहा है कि जब मामला कोर्ट के न्यायाधीन है तो उसके लिये हम कुछ नहीं कर सकते । लेकिन इतनी बात जरूरी है कि टाटा की जमींदारी हो या किसी और की जमींदारी हो इसके हम विरोधी हैं (*Interruptions*)

श्री प्रकाश महरोत्रा : क्या आप इन लोगों को कोई मजदूरी फिक्स करेंगे ?

श्री धनिक लाल मंडल : ये लोग लोहे के टुकड़े चुनते हैं और फिर उनको बाजार में बेचते हैं । ऐसी हालत में उनको वेतन देने की बात कैसे हो सकती है । वे लोग किसी के मजदूर नहीं हैं ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : क्या आप कन्ट्रैक्ट सिस्टम को हटाएंगे ?

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने अपने मूल बयान में कहा है कि यह मामला विचाराधीन है ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : श्रीमन्, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं . . .

REFERENCE TO ALLEGED UNEARTHING OF FAKE PASSPORT AND VISA RACKETEERS IN DELHI

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH (KULKARNI): Now we are starting with special mentions. Yes, Mr. Shiva Chandra Jha. Please be specific.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत की राजधानी इस दिल्ली में जाली पासपोर्ट और जाली वीजा बनाने का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है । यह बहुत हैरानी और आश्चर्य की बात है कि ठीक केन्द्रीय सरकार की आंखों के सामने इस तरह की चीज हो रही है । जैसा कि अखबारों में समाचार आया है, इस सिलसिले में दो गिरोह पकड़े गये हैं जो कि लोगों को ईरान भेजने के लिए जाली पासपोर्ट बनाते थे । जो लोग ईरान में काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनसे एक-एक पासपोर्ट के लिए तीन-तीन हजार रुपये लिये जाते हैं । इस बारे में दिल्ली की पुलिस ने 12 आदमियों को गिरफ्तार किया है और 343 पासपोर्ट जब्त किये गये हैं । श्रीलंका के नाम से दिल्ली में पासपोर्ट छापे जाते थे और जो लोग हिन्दुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिये ये जाली पासपोर्ट बनाये जाते हैं । ये आम तौर पर ऐसे लोग हैं जो तस्कर व्यापार में लगे हुए हैं । श्रीलंका के पासपोर्ट और ईरान के पासपोर्ट के सम्बन्ध में यह सिलसिला चल रहा है । यह बड़ी हैरानी की बात है कि देश की राजधानी में यह सिलसिला चल रहा है । ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को यह भान हो गया है कि भारत सरकार ने पासपोर्ट